International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(I), July - September, 2024, pp. 117-122

उच्च शिक्षा के बाजारीकरण के संबंध में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रिंकू मीना*

सार

भारत ऋग्वेद काल से लेकर मौर्य काल तक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरू रहा है। हमें वेदों, ग्रंथों, एवं शास्त्रों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि हमारे देश में शिक्षा अर्जन के विश्व प्रसिद्ध केंद्र जैसेः नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय रहे है, जिनमें हजारों देश–विदेश के विद्यार्थी एवं शोधार्थी अध्ययन करते थे। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के साथ–साथ योगा, आध्यात्म, सामाजिक जीवन शैली आदि के बारे में भी बताया जाता था। लेकिन कालांतर में मुस्लिम/विदेशी आक्रमण के कारण इन शिक्षा केन्द्रों को नष्ट कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज अधिकांश शिक्षण संस्थान मात्र धन अर्जन के केन्द्र बन गए है जहाँ पर शुल्क, बाहरी गतिविधियां, अनुदान आदि के नाम पर लाखों लाख रूपये लिए जा रहे हैं। माता–पिता बड़ी मुश्किल से पैसे की व्यवस्था कर इन संस्थानों में अपने बच्चों का प्रवेश करा पाते हैं कई बार शिक्षण संस्थानों, राजनैतिक, एवं भ्रष्ट अधिकारियों के मेल–जोल के कारण पेपर आउट, परीक्षा स्थगत आदि करा लिए जाते हैं। जिसके कारण भर्तियां निरस्त हो जाती है या न्यायालय में चली जाती है और सामान्य विद्यार्थी के कठिन मेहनत करने के बाद भी असफलता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप योग्य विद्यार्थी को बेरोजगारी, मानसिक तनाव आदि का सामना करना पड़ता है कई बार तो विद्यार्थी मानसिक तनाव में आत्महत्या का रास्ता भी अपना लेते हैं। हाल ही में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 13089 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। इस पत्र में इन समस्यों पर चर्चा की गई है। इनको दूर करने के उपाय सुझाये गए।

शब्दकोशः *विद्यार्थी, शिक्षण संस्थान, भ्रष्टाचार।*

प्रस्तावना

मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा, आवास के बाद अगर किसी का सबसे अधिक महत्व है तो वो शिक्षा है क्योंकि शिक्षा के कारण ही व्यक्ति में सोच, समझ, तर्क–वितर्क, उचित–अनुचित की समता विकसित करती हैं। यह शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक या उच्च स्तर की हो सकती है। विशेष विषय में दी जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा प्रायः ऐच्छिक होती है। इसके अंतर्गत स्नातक स्नाकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि शामिल है। उच्च शिक्षा के आधार पर व्यक्ति अपनी आजीविका का चयन करता है जैसे निजी व्यवसाय पेशेवर नौकरी (डॉक्टर, इंजीनीयर) प्रशासनिक नौकरी (IAS RAS PCS) आदि।

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

स्वतंत्रता के बाद से 1980 के दशक के अंत तक अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी नियंत्रण में थे, 1980 के बाद से उच्च शिक्षा में उदारीकरण की शुरूआत हुई जिसके के कारण तेजी से निजी विश्वविद्यालय व तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई। विगत् 50 वर्षों में देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में 11.9 गुना वृद्धि हुई हैं जिनमें से निजी संस्थानों की संख्या अधिक हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या देश की जनसंख्या के अनुपात में कम है, जिसके कारण अच्छे शिक्षण में प्रवेश पाना भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा बन गया है। सरकारी संस्थानों में शुल्क कम है लेकिन सीमित संख्या में पद होने के कारण निजी संस्थानों में प्रवेश लेना पड़ता हैं इन संस्थानों की शुल्क बहुत अधिक होती है, जो प्रति सेमेस्टर 25000 रूपये से लेकर कई लाखों तक होती है। जब किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिल पाता है तब निजी कोटे में प्रवेश दिया जाता बदले में अनुदान के नाम पर विद्यार्थी से लाखों रूपये लिए जाते हैं। उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसेः– IIT MBBS आदि के संस्थानों की संख्या सीमित हैं। इसलिए इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल सके इसलिए विद्याार्थी कोचिंग का सहारा लेते है। इन कोचिंग संस्थानों की शुल्क कई लाखों में रहती है, शुल्क के अतिरिक्त बड़े शहरों में रहने–खाने का खर्चा बहुत अधिक होता है।

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2021–2022 के अनुसारः–

- **छात्र नामांकनः** उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन की संख्या वर्ष 2020–21 तक 4.33 करोड़ थी, जो वर्ष 2020–21 में 4.14 करोड़ और वर्ष 2014–15 में 342 करोड़ उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है इन नामांकित में महिलाओं की संख्या वर्ष 2021–22 तक 2.07 करोड़ थी, जो वर्ष 2014–15 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। स्नातकोत्तर पर नामांकित महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की तुलना में अधिक हैं, जो कुल नामांकन का 55.4 प्रतिशत है। सकल नामांकन अनुपात (GER) 18–23 आयु वर्ग के लिए (GER) 28.4 प्रतिशत है।
- **विषय–वार नामांकनः** वर्ष 2021–22 में स्नातक स्तर पर, कला (BA) में सबसे अधिक नामांकन 34.2 प्रतिशत विज्ञान (BSC) में नामांकन 14.8 प्रतिशत वाणिज्य (B.COM) में नामांकन 13.3 प्रतिशत और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (B.TECH) में नामांकन (11.8) प्रतिशत था। स्नातकोत्तर स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे अधिक नामांकन लगभग 10.8 लाख छात्र देखा गया । शोध या पीएचडी स्तर पर इंजीनियरिंग विषय में सबसे अधिक नामांकन देखा गया, जिसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का स्थान है।

उच्च शिक्षा से संबंधिति समस्याएं एवं चुनौतियाँ

भारत में सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाना व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। सरकार द्वारा जीडीपी का 2.7 प्रतिशत भाग ही शिक्षा पर व्यय किया जाता है। शिक्षा पर खर्च में भारत दुनिया में 136 वें स्थान पर आता है। नीचे विश्व के बड़े देशों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले खर्चे का विवरण दिया गया है। जो इस प्रकार हैः–

देश	GDP	शिक्षा पर खर्च	हिस्सेदारी
नॉर्वे	28.97	1.87	6.38%
न्यूजीलैड	14.95	1.00	6.31%
ब्रिटेन	190.47	11.87	6.23%
अमेरिका	1408.34	85.77	6.09%
ऑस्ट्रेलिया	96.12	5.72	5.9%
फ्रांस	187.57	9.75	5.20%
जर्मनी	267.09	11.27	4.22%
जापान	353.86	14.43	4.08%
भारत	188.66	4.41	2.7%

(जीड़ीपी और खर्च के आंकड़े लाखों करोड़ रूपये में) –भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या अत्यंत कम है।

- उच्च शिक्षण संस्थानों की शुल्क बहुत अधिक है।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के शुल्क हेतु बैंक से मिलने वाले ऋण 20 वर्ष तक की उदार पुनर्भुगतान अवधि के लिए प्रदान किये जाते हैं। इस ऋण की ब्याज दर 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष से शुरू होती है। यह ब्याज दर अधिक है।
- विश्व के शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत का कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं आता है। परिणाम स्वरूप भारत से बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अन्य देशों में जाते हैं। चीन के बाद भारत के विद्यार्थी सबसे अधिक संख्या में विदेशों में जाते हैं।
- भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में तनाव का माहोल बहुत अधिक रहता, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, विशेषकर उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रवेश को लेकर जैसेः– IIT, MBBS आदि। NCRB द्वारा विगत वर्षों में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी का डाटा जारी किया गया है,जो कि इस प्रकार है–

पिछले पांच वर्षों में छात्रों की आत्महत्याएं

वर्ष	कुल छात्र आत्महत्याएं	पुरूष छात्रों की आत्महत्याएं	महिला छात्रों की आत्महत्याएं
2017	9905	59.71%	47.56%
2018	10159	52.85%	47.15%
2019	10335	53.82%	46.17%
2020	12526	55.62%	44.38%
2021	13089	56.51%	43.49%

- परिक्षाओं के असंगत प्रश्नों एवं विवादित उतरकुंजी को लेकर विद्यार्थी का आक्रोश होना। इन असंगत प्रश्नों एवं विवादित उतरकुंजी के आपत्ति हेतु परीक्षा संस्था द्वारा प्रत्येक प्रश्न 100–200 रूपये का शुल्क लिया जाता है। कई परिक्षाओं में 20–30 विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को 2000–3000 रूपये देने पड़ते हैं, जो एक सामान्य परीक्षार्थी के अवहनीय होता है। कई बार इन परीक्षाओं के लेकर न्यायालय में जाना पड़ता है, जिसके कारण भर्तियां सालों–साल लंबित होती रहती हैं। जिसके कारण एक परीक्षार्थी को मानसिक तनाव एवं आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता हैं।
- पेपर लीक पेपर माफिया की मिलीभगत के कारण विगत् 5 सालों में 65 से अधिक पेपर लीक हुए। पेपर लीक के कारण भर्तियां निरस्त हो जाती हैं परिणामस्वरूप योग्य विद्यार्थी आयु सीमा समाप्त, बेरोजगारी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को झेलना पड़ता है। एक विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में लाखों रूपये देकर तैयारी करता है और जब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया उस पर क्या गुजरती है इस पीड़ा को केवल वही महसूस कर सकता है।
- उच्च शिक्षा अर्जन में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की तुलना में बहुत कम होना। उच्च शिक्षा की पहुंच ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं तक अच्छी है जिसके कारण केवल 19.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं।
- भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थिओं का सर्वांगीण विकास करने में असफल होना।
- असमान पहुँच और निम्न ळम्तः सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर उल्लेखनीय असमानताएँ पायी जाती हैं। भारत का GER वर्तमान में 28.4 प्रतिशत जो वैश्विक औसत 36.7 प्रतिशत से नीचे हैं।
- भारत में शिक्षा के लिये अंतरिम बजट 2024–25 में 7 प्रतिशत की कटौती की गई है और विश्वविद्यालय अनुदान के लिए आवंटन में 61 प्रतिशत की कटौती की गई हैं।

- भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश अभी भी पर्याप्त कम है 0.64 प्रतिशत है, जो चीन 2.4 प्रतिशत, जर्मन 3.1 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया 4.8 प्रतिशत और सयुंक्त राज्य अमेरिका 3.5 प्रतिशत जैसे देशों से बहुत पीछे हैं।
- भारत उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की भारी कमी का सामना कर रहा है। वर्ष 2023 तक की स्थिति के अनुसार, भारत के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30 प्रतिशत से अधिक शिक्षण पद रिक्त बने हुए हैं। बेहतर अवसरों और पारिश्रमिक के लिए प्रतिभाशाली शिक्षाविदों का अन्य देशों या निजी क्षेत्र की ओर पलायन एक गंभीर चुनौती है।
- भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योग के बीच प्रभावी सहयोग का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण स्नातकों में कौशल अंतराल पैदा हो रहा है।

चर्चा एवं सुझाव

वर्तमान में तेजी से वैश्वीकृत और विकसित होती दुनिया में उच्च शिक्षा के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है क्योंकि उच्च शिक्षा के कारण शिक्षार्थियों में उन्नत ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और विश्लेष्णात्मक कौशल प्रदान करती है। उच्च शिक्षा शिक्षार्थियों के सफल भविष्य बनाने में सक्षम बनाती है साथ ही शिक्षार्थियों को निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देती है एवं निरंतर विकसित होती दुनिया के प्रति अनुकूलनशील बनाती है। इसलिए वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा शिक्षार्थियों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, आवश्यकताओं को पूरा कर सके एवं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। विश्वविद्यालयों की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए इनमें परियोजना आधारित शिक्षा रटन विद्या के बजाय व्यावहारिक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में एनजीओ की सहायता से छात्रों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी एवं नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान मात्र डिग्री प्राप्ति के केंद्र ना रह कर कौशल सृजनकर्ता के रूप में विकसित किए जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को उन्नत करना और मुक्त शैक्षिक संसाधनों के विकास एवं अंगीकरण को बढ़वा देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री और व्याख्यानों तक निःशुल्क पहुँच प्रदान हो सके।

भारतीय विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में उद्यमिता एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना किए जाना चाहिए। ताकि छात्रों के नवोन्मेषी विचारों को सफल उद्यमों में बदलने के लिये मार्गदर्शन वित्तपोषण के अवसर तथा सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान हो सके। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना, जहाँ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान संयुक्त डिग्री ट्विनिंग कार्यक्रमों या शाखा परिसरों की पेशकस करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहकार्यता स्थापित कर सके जिससे भारतीय उच्च शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकेगा। दोहरे अध्ययन कार्यक्रमों (Dual study program) सैद्वांतिक शिक्षा को कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ संयुक्त कर सकें। इससे विद्यार्थियों की रोजगार–क्षमता बढ़ेगी एवं कंपनियों के लिए कुशल कार्यबल भी उपलब्ध हो सकेगा।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाना वाले व्यय को बढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को कम लागत पर गुणवता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके साथ ही शिक्षण संस्थानों में अच्छा आधारभूत संसाधन मिल सके। नये उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थी को अपने नजदीकी स्थान पर उच्च शिक्षा मिल सके। उच्च शिक्षण संस्थानों की शुल्क को सरकार द्वारा विनियामक किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी वहन कर सके है साथ ही उच्च शिक्षा ऋण की ब्याज दर कम की जानी चाहिए। कोचिंग संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवता में सुधार किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक उच्च शिक्षण संस्थानो से प्रतिस्पर्धा कर सके जिसके परिणाम भारत के विद्यार्थी विदेशों में गमन हो तथा विदेशी विद्यार्थी भारत

में अध्ययन हेतु आए। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैकिंग एवं तनाव का माहोल समाप्त किया जाए ताकि विद्यार्थी आत्महत्या न करे।

प्रतियोगिता परिक्षाओं एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ताकि योग्य विद्यार्थी का चयन हो, ऐसे प्रश्न–पत्र एवं उतरकुंजी बनाए ताकि विवाद कम से कम हो ओर विद्यार्थियों को न्यायालय के चक्कर ना काटने पड़े पेपर लीक की समस्या को लेकर मजबूत कदम उठाना चाहिए जिससे विद्यार्थी को बेरोजगारी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को ना झेलना पड़े।

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा की गई पहल

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:– इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है, जहाँ बहु–विषयक शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान एंव नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एवं वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- इंस्टिट्यटू ऑफ एमिनेसं (Institution of Eminence IOE) योजना के ऐसे 20 संस्थानों का चयन किया जाना चाहिए था जो पूर्ण स्वायत्ता का उपभोग कर सकते थे।
- नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कः– इसे शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षण और कौशल विकास को एकीकृत करने के लिये संरचना किया गया है
- संशोधित प्रत्यायन एंव रैकिंग प्रणालीः– इसके तहत भिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैकिंग दी जाती है। संस्थानों के गुणवत्ता मानकों का मानक निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का पुनर्गठन किया गया है।
- स्वयंः– यह ऐसा मंच है जो प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराता है।
- भारतीय राष्ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरीः– यह उच्च शिक्षा से संबंधित विस्तृत शिक्षण सामग्री ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करता है।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रमः– यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों के लिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिये आकर्षित किया जाता है इसके अंतर्गत विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- इन्सपाइर के तहत शी कार्यक्रमः–विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंस्पायर योजना की शुरूआत की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान कर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर मौलिक एवं प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने और शोध भविष्य बनाने के लिये छात्रों को आकर्षित करना है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा मनुष्य के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह मनुष्य को और से अलग बनाती है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को सभ्य एवं अनुशासित बनाती है। उच्च शिक्षा बौद्धिक विकास के साथ–साथ रोजगार प्राप्ति में सहायक है। आज वैश्विक तकनीकी के युग के अनुसार ऐसे नए शैक्षणिक दृष्टिकोण, उन्नत प्रौद्योगिकी और शोध के अवसर लाने की आवश्यकता है, जिससे भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार हो। शिक्षा व्यक्ति का मूल अधिकार है, इसलिए यह सभी की पहुँच में वहनीय होनी चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी जो सभी छात्रों, संस्थानों और व्यापक समाज को लाभान्वित करे।

सदंर्भ ग्रन्थ सूची

1. रॉय चौधरी, सुनंदन (2017), भारत में राजनीति, नीति और उच्च शिक्षा
2. पवन अग्रवाल (2009). भारतीय उच्च शिक्षा भविष्य की कल्पना SAGE प्रकाशन।
3. द हिंदू में दिनाकं 18.05.2024 को प्रकाशित ''The hyperpoliticisation of Indian higher education'' लेख।
4. द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर में।
5. शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर जारी रिपोर्ट 2020–2021।

❖◆❖